RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-06
June -2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

बिहार में भारत छोड़ो आन्दोलन और किसान सभा

डॉ0 रंजीत कुमार

द्वितीय विश्वयुद्ध ने सभी भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक–आर्थिक दलों के सामने एक नयी समस्या खड़ी कर दी थी। अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों ने उन्हें नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया था। स्वामी सहजानंद इसके अपवाद नहीं थे। इस प्रक्रिया में वे अपने को ज्यादा–से–ज्यादा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सवालों पर व्यस्त रखते थे। सुभाषचन्द्र बोस और स्वामी सहजानन्द का विचार था कि युद्ध का फायदा उठाकर गाँव–गाँव में स्वयंसेवक सेना बना ली जाए जो विजयी होने पर जापान से और दगाबाजी करने पर अंग्रेजो से और सत्ता के हस्तांतरण के समय शासक वर्ग से लड़ती।[1] 19 और 20 मार्च को रामगढ़ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गाँधी जी ने बोलते हुए कहा कि यदि कोई संघर्ष शुरू करना चाहता था तो वे उसकी राह में नहीं आना चाहते थे, किन्तु उसे कांग्रेस के बाहर से वैसा करना होता। यदि वह कांग्रेस में रहना चहता तो कांग्रेस के कार्यक्रम और उसकी नीति का पालन करना होगा। गाँधी ने आगे कहा, "सत्य और अहिंसा सत्याग्रह की आत्मा है और चरखा उनके प्रतीक है। सत्य, अहिंसा और चरखा में बिना पूरी निष्ठा के आप मेरे सैनिक नहीं हो सकते, और मैं फिर उसे दुहराऊँ कि यदि आप इसमें विश्वास नहीं करते तो आप मुझे छोड़ दें और अपने तरीके स्वयं ही आजमाएँ।"

वामपंथी राजनीतिक विचार रखने वाले कुछ भारतीय राष्ट्रवादी उन दिनों युद्ध संकट कं संदर्भ में कांग्रेस के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। इसमें अधिकतर अग्रगामी दल के लोग थे। ये कांग्रेस से ब्रितानी सरकार के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करने का रवैया अपनाने की माँग कर रहे थे। अपने रवैयों और नीति के समर्थन में आन्दोलन संगठित करने हेतु उन्होंनें अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान आयोजित किया। सहजानन्द सरस्वती इसकी स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव सहजानन्द सरस्वती द्वारा प्रस्तुत किया गया। सरदार सारदूल सिंह ने उनका अनुमोदन किया तथा कुछ अन्य लोगों ने उसके समर्थन में भाषण किये। उनमें कांग्रेस की नीति की कड़ी आलोचना की गयी थी तथा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने हेतु भारतीय जनता के अधिकार पर बल दिया गया था। इस प्रस्ताव में अप्रैल 6 से स्थानीय संघर्षों को तीव्र बल देने, अखिल भारतीय पैमाने पर संघर्ष शुरू करने का आह्वान भारतीय जनता के युद्ध में भाग लेने से अलग रहने तथा भारत की स्वतंत्रता हासिल करने हेतु अंतिम संघर्ष करने का संकल्प को दोहराया गया।

आन्दोलन में किसानों की तत्क्षणिक मांगो का भी समर्थन किया गया था। ये मांग थी– मालगुजारी राजस्व एवं नहर कर में 50 प्रतिशत की छूट, जमींदारी एवं वैसी अन्य व्यवस्थाओं का बिना मुआवजा के समाप्ति।

स्वामी सहजानन्द अपने स्वागत भाषण में काफी आक्रमक हो गये थे उन्होनें घोषणा की, "अब समय गंवाने का नहीं रह गया है और हमलोग काफी सतर्क हैं कि सभी दासात्मक कदमों को खोजकर और रोक कर सीधी कार्रवाई के लिए तुरंत ठीक कर लें और तभी केवल हम इस लायक होगें कि राष्ट्र को कुजात आक्रमण और दुश्मन के सामने घुटने टेकने से बचा सकते हैं।"[2]

इसी के तुरंत बाद प्लासा में 9 अप्रैल, 1940 को अखिल भारतीय किसान सभा के पंचम अधिवेशन में समझौता विरोधी राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और मध्य अप्रैल में सहजानन्द की गिरफ्तारी हुई। सहजानंद इस समय भी पहले की तरह किसान सभा के महासचिव थे और इस हैसियत से प्लासा अधिवेशन में शरीक हुए। यहीं पर युद्ध के विषय पर और राष्ट्रीय संग्राम पर अंतिम समझौता विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया जो प्लासा और नागपुर प्रस्ताव के पहले था जिसमें यह नीति बदली गयी। युद्ध प्रयास के विरोध में की गयी गिरफ्तारी की बढ़ती हुई संख्या में सहजानंद की गिरफ्तारी केवल एक थी। स्वामी सहजानन्द के जेल चले जाने से किसान आन्दोलन की भारी क्षति हुई। फिर भी पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, चंम्पारण, पूर्णिया, पलामू और संथाल परगना जिलों में किसान सभा का बहुत कुछ काम चल रहा था। 1 सितम्बर,1940 को प्रान्त में कई स्थानों पर किसान दिवस मनाया गया। इसके लिए सभाएं की गयी और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, बाबा सोहन सिंह की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किया गया। बिहार किसान सभा के नेता की अनुपस्थिति में वामपंथी पार्टियों तथा अग्रगामी दल, कांग्रेस समाजवादी और साम्यवादी दल की विभिन्न शाखाएँ फिर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न कर रहीं थीं। स्वामी सहजानंद के जेल जाने के समय यमुना कार्यी की अध्यक्षता में अग्रगामी दल का उस पर नियंत्रण था। डुमरांव में 9 मार्च,1941 को बिहार किसान सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर कांग्रेसी समाजवादियों ने किसान सभा–संगठन पर अपना

RRIJM 2015, All Rights Reserved

नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।[3]

बिहार प्रान्त किसान सभा की संघर्ष समिति की एक बैठक 24 नवम्बर को हुई। उसमें निर्णय किया गया कि 21 दिसम्बर को को गन्ना दिवस मनाया गया जाए। इसका मकसद गन्ना मूल्य निश्चित करने के साथ किसानों की मांगों को पूरा कराना था। अन्य प्रस्तावों में रूस के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गयी थी। देहली के नजरबंदियों की रिहाई की मांग की गयी थी और स्वामी सहजानंद के नेतृत्व वाली किसान सभा का समर्थन करने का आह्वान किया गया था। 20 नवम्बर को अखिल भारतीय किसान सभा के प्रभारी अध्यक्ष जगजीत सिंह पंजाबी पटना आये। उन्होनें स्वयंसेवकों का संगठन बनाने की योजना पर कई सदस्यों से बातचीत की।

इस बीच डुमराँव राज्य की ओर डुमराँव स्थित किसान सभा का भवन जब्त कर लिया गया। इससे शाहाबाद जिले में स्थिति उत्तेजनापूर्ण हो गयी। डुमंराव और अन्य स्थानों पर इसके विरोध में सभांए हुई। मुंगेर और भागलपुर के इलाकों में भी किसानों की सभाएँ हो रही थी। अनेक किसानों ने 01 जनवरी,1942 ई0 को डुमरांव में सत्याग्रह शुरू कर दिया।[4]

किसान सभा की एक दूसरी शाखा युद्ध–प्रयत्नों में सहायता देने के विरूद्ध थी। इसके नेता ग्राम सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक दल का संगठन कराना चाहते थे। इस समय तक सहजानन्द गुट सरकार को पूर्ण सहयोग देने की नीति का प्रतिपादन कर रहे थे। 09 मार्च, 1942 को स्वामी सहजानन्द हजारीबाग जेल से रिहा होकर पटना आये।[5]

स्वामी सहजानन्द अपनी 3 वर्ष की पूर्ण सजा काटने के एक साल पहले ही छोड़ दिये गये थे। इस समय तक दो महत्वपूर्ण घटनाएँ घट चुकी थी। किसान सभा पर फारवर्ड ब्लॉक और कम्युनिस्टों को नेतृत्व स्थापित हो चुका था। इसके एक नेता मथुरा प्रसाद मिश्र बिहार प्रदेश किसान सभा के सचिव थे। दूसरी ओर, जेल में स्वामी ने मार्क्सवाद का गहन अध्ययन और मनन किया। इसके चलते 1939 ई0 से उनके मस्तिष्क में शुरू हुई प्रक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुँची। स्वामी सहजानन्द कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य तो नहीं हुए, किन्तु चिन्तन और व्यवहार के स्तर पर वे कट्टर मार्क्सवादी हो गये थे। 8 सोवियत संघ पर नाजी आक्रमण ने स्वामीजी को अपनी नीति पर पुनर्विचार के लिए मजबूर किया। स्वामी सहजानन्द के शब्दों में,"जब हम जेल गये थे तो यही मानते थे कि इस यूरोपीय महायुद्ध के खिलाफ हमें युद्ध करना है और इस प्रकार अंग्रेजी सरकार के युद्धोधोग में जहाँ तक हो सके, बाधा पहुंचानी है। इसे ही अंग्रेजी में "वार एगेन्सट वार" कहते हैं। मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के लेखों तथा मंतव्यों से हमने यही सीखा था कि सम्राज्यवादी युद्ध को सफल न होने देना। फलतः वहाँ (जेल में भी) हमारी यही धारणा तब तक बनी रही जब तक हिटलर ने रूस पर हमला नहीं किया। हमले के एक सप्ताह बाद ही यह ख्याल जड़ से बदल गया। 21 जून, 1941 के एक सप्ताह बाद, हिटलर का आक्रमण हुआ और जून बीतते–न–बीतते हम स्वतंत्र रूप से बिना किसी से पूछे या वाद–विचार किए ही इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें अब वह सिद्धांत छोड़ना ही होगा। हिटलर और उसकी गत दो वर्षों की सामरिक गतिविधि के सूक्ष्म पर्यवेक्षण ने हमें ऐसा सोचने एवं निश्चय करने को बाध्य किया।"[6]

स्वामी सहजानन्द के जेल–जीवन के बीच ही अखिल भारतीय किसान कौंसिल ने आन्ध्र प्रदेश के पकाला में अक्टुबर,1941 में और 13 फरवरी,1942 को युद्ध–संबंधी दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पकाला में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया, सन् 1942 ई0 के 8 मार्च को स्वामी सहजानन्द जेल से रिहा हुए।[7] कांग्रेस सोशलिस्टों ने तो उनका साथ पहले ही छोड़ दिया था, धीरे–धीरे फारवर्ड ब्लॉक वालों से भी उनका संबंध ठीक नहीं रह रहा था। दोनों के युद्ध–विरोधी विचारों में गहरे मतभेद के कारण यह स्वाभाविक था। अखिल भारतीय किसान सभा के विध्य सम्मेलन में फारवर्ड ब्लॉक के कुछ लोगों ने किसान सभा द्वारा नागपुर प्रस्ताव को फिर से समर्थन देने का हंगामे के साथ विरोध भी किया।[8] स्वामी सहजानन्द इस बार फिर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हुए।

स्वामी सहजानन्द के जेल से निकलने के एक महीने के ही अन्दर गया जिले के शेरघाटी में 4–5 अप्रैल, 1942 को बिहार प्रदेश सभा का 9वाँ सम्मेलन हुआ जिसके सभापति स्वामी सहजानन्द हुए।[9] सरकारी सूत्रों के अनुसार, किसानों की उपस्थिति और उसके उत्साह के अनुसार यह एक सफल सम्मेलन था। यद्यपि फारवर्ड ब्लॉक वालो तथा सोशलिस्ट ने काले झंडे दिखाये और सभा को भंग करने की भी कोशिश की, किन्तु इसमें नाकामयाब रहें।[10]

डुमरांव सम्मेलन में बिहार प्रदेश किसान सभा से अलग होने के बाद समाजवादी भी किसानों को अपने नेतृत्व में लाने की हर कोशिश करने लगे। अप्रैल,1942 में रामवृक्ष बेनीपुरी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छोटी–छोटी किसान सभाएँ संगठित कर रहे थे। इन सभाओं में नागपुर प्रस्ताव की निंदा की जा रही थी। 18 और 19 अप्रैल को मुजफ्फरपुर जिले के पातेपुर में समाजवादी किसानसभा के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता अब्दुल हयात चांद ने की तथा इसके अन्य वक्ताओं में वसावन सिंह और रियासत करीम थे। उस सभा में वरडीहातुर्की के लालदेव राय ने भी युवाओं के जत्था का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी भागीदारी की। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों दलों के नेता मई,1942 में अखिल भारतीय किसान सभा के वार्षिक सम्मेलन के आयोजन के लिए सब तरह के प्रयास

RRIJM 2015, All Rights Reserved

में लगे हुए थे। स्वामी सहजानन्द के दल की सभा बिहार में होने वाली थी और समाजवादियों की मुजफ्फरपुर में।[11] किन्तु जहाँ मई के दूसरे सप्ताह में बिहार में इन्दुलाल याज्ञिक की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का वार्षिक अधिवेशन फारवर्ड ब्लॉक और समाजवादियों द्वारा उपद्रव मचाने की कोशिश के बावजूद 30 मई,1942 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, वहीं मुजफ्फरपुर के बेदौल में प्रस्तावित समाजवादियों की अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मेलन को स्थगित कर देना पड़ा।[12] बिहार में नागपुर प्रस्ताव को एकमत से पारित कर दिया गया। सरकारी रपट के अनुसार, अब अखिल भारतीय किसान सभा पर कम्युनस्टिों का पूर्ण वर्चस्व था। इसके मूल में तुरंत जेल से रिहा हुए सुनील मुखर्जी का हाथ था। समाजवादी दल के नेतृत्व में प्रस्तावित सम्मेलन के आयोजन के पूर्व ही समाजवादियों और फारवर्ड ब्लॉक में फूट हो गयी और एक प्रमुख किसान नेता धनराजपुरी को समाजवादियों ने अपनी सभा से निकाल भी दिया।[13]

1942 के 9 अगस्त की 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की शुरूआत तथा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी ने घटनाओं को एक नया मोड़ दिया। ज्ञातव्य है, बिहार प्रान्त भारत छोड़ो आन्दोलन का सर्वप्रमुख केन्द्र था। यहाँ का आन्दोलन संगठित कम था, किन्तु भारत में सर्वाधिक सशक्त था। स्वामी सहजानन्द जैसे नेता के लिए इस आन्दोलन ने बड़ी ही असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी। यद्यपि स्वामी सहजानन्द बहुत पहले से युद्ध–प्रयत्नों में ब्रिटिश सरकार के समर्थन के पक्षधर थे, किन्तु ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति का समर्थन करना उनके स्वभाव के विपरीत था। वे हमेशा कांग्रेसी नेताओं की रिहाई की मांग करते रहे। उन्होनें महात्मा गांधी की रिहाई के लिए सरकार के पास अपील की। दूसरी तरफ, सरकारी अधिकारियों को उनपर पूरा विश्वास नहीं था। उनके अनुसार, यद्यपि स्वामी सहजानन्द किसानों को प्रदर्शन और वकाश्त संघर्ष नहीं करने की सलाह दे रहे थे, किन्तु गुप्त रूप से गया के भावली क्षेत्र के किसानों को वकाश्त जमीन की फसल काट लेने की भी उकसा रहे थे।[14]

स्वामी सहजानन्द और उनके कम्युनिस्ट साथियों के नेतृत्व में बिहार प्रदेश किसान सभा की सभांए, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जा रही थी, किन्तु इन सबों में ब्रिटिश युद्ध प्रयत्नों को समर्थन देने, तोड–फोड़ न करने तथा फसल न लूटने की सलाह दी जा रही थीं किसानों से कहा जा रहा था कि अभी जर्मनी और जापान को हराने के लिए किसान सभा हर संभव प्रयत्न कर रही है। उनकी पराजय के बाद ही यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता–संग्राम की लड़ाई भीषण रूप से शुरू करेगी। दूसरी ओर सभा किसानों के लिए गया जिले में प्रशिक्षण भी दे रही थी। प्रशिक्षण देने वालों में स्वामी सहजानन्द और राहुल सांकृत्यायन के अतिरिक्त अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः वंकिम मुखर्जी और इन्दुलाल याज्ञिक भी थे।[15]

बिहार प्रदेश किसान सभा के नेतृत्व की इतनी क्रियाशीलता के बावजूद उसकी लोकप्रियता कम होती गयी। इसक प्रमाण किसान सभा के सोनपुर में आयोजित 10वें वार्षिक सम्मेलन में किसानों की उपस्थिति में कमी से मिलता है।12 और 13 जून,1943 को सोनपुर में हुए इसके सम्मेलन में मात्र 700 किसान उपस्थित थे। इस सभा के पारित प्रस्तावों में एक प्रमुख प्रस्ताव था, कृषक–मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि तथा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अनाज के रूप में उसकी मजदूरी का भुगतान। इस सम्मेलन ने अगस्त विद्रोह के लिए सरकार को पूरी तरह उत्तरदायी बताते हुए कांग्रेसी नेताओं को तुरंत छोड़ देने की सलाह दी।[16]

बिहार के किसान स्वामी सहजानन्द और बिहार प्रदेश किसान सभा की सलाह मनाने को तैयार न थे। 09 अगस्त के बाद तो बिहार के कई क्षेत्रों के किसान जैसे बावले हो उठे थे। एक ओर उनके आक्रमण के केन्द्र बिन्दु डाकतार तथा रेलवे की लाइनें थी तो दूसरी ओर जमींदारी, सूद–खोर, महाजन और अनाज की चोर–बजारी करने वाले व्यापारी भी थे। बिहार के कई भागों में जमींदारों की कचहरियां जला दी गयी और उनके गुमास्तो की हत्या कर दी गयी। जमुई क्षेत्र में जमींदारी के तहसीलदार इतने डर गये थे कि वे गवाही देने के लिए तैयार न थे। सरकार के अनुसार, जमींदारों के दस्तावेजों की बर्बादी से काश्तकारों को बहुत फायदे थे। संथाल परगना के किसान भी इनमें पीछे नहीं थे। वहाँ भी परगनैत को लूटा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और जब संथालों को गिरफ्तार करने पुलिस गयीं तो उस पर भी तीर–धनुष से आक्रमण किया गया। परिणाम यह हुआ कि पुलिस बल को पीछे हटना पड़ा तथा बंदी उनकी गिरफ्त से भाग निकले।[17] 05 जून,1943 तक सम्पूर्ण बिहार जल रहा था। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि शुरू में जिन कुछ छोटे–छोटे जमींदारों और धनी किसानों ने विद्रोह में भाग लिया था। वे भी सम्पत्ति की कुर्की–जब्ती के आदेश और उसको कड़ाई से अमल में लाने के कारण जल्दी ही ठंडे पड़ गये। भागे हुए और छिपे हुए लोगों ने जल्द ही आत्मसमर्पण कर दिया।[18] यूं तो हर जगह उच्च वर्ग के लोग, खासकर अधिकांश छोटे–छोटे जमींदारों, जो 1942 के अंतिम दिनों से ही सरकार के प्रति अपनी वफादारी का राग अलाप रहे थे और लूट–पाट तथा अन्य विध्वंसक कार्यों के लिए गुंडों और बाहरी तत्वों को दोषी ठहरा रहे थे।

अखिल भारतीय किसान सभा के मार्च, 1944 के विजयवाड़ा अधिवेशन में स्वामी सहजानन्द इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यहां भी कम्युनिस्टों से बढ़ती हुई दूरी स्पष्ट दिखलाई पड़ रही थी। लेकिन, अप्रैल 1945 के अखिल

RRIJM 2015, All Rights Reserved

भारतीय किसान सभा के दसवें अधिवेशन में स्वामी सहजानन्द और बिहार के उनके सहयोगियों ने भाग नहीं लिया। बिहार से कोई दूसरा अखिल भारतीय किसान कौंसिल का सदस्य भी उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि बिहार प्रदेश किसान कौंसिल ने अखिल भारतीय किसान कौंसिल के प्रतिनिधि के चुनाव पर निषेधाज्ञा लागू कर दी थी।[19] यह कम्युनिस्ट पार्टी और स्वामी सहजानन्द के बीच अंतिम टूट थी।

सन्दर्भ सूचीः–

01. चन्द्रभूषण; किसान आन्दोलन का विकास, वाराणसी, 1986, पृ0 149.
02. स्वामी सहजानंद सरस्वती; अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के स्वागत समिति के चेयरमैन का भाषण, रामगढ़ स्वागत समिति, 1940, पृ0 14–15.
03. बिहार सरकार, प्रथम पखवारे की पाक्षिक रपट, मार्च 1941.
04. बिहार सरकार, प्रथम पखवारे की पाक्षिक रपट, मार्च–1942.
05. वही.
06. स्वामी सहजानंद सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष 1982 पृ0 345.
07. वही पृ0 388.
08. एम0 ए0 रसूल; ए हिस्ट्री ऑफ द ऑल इण्डिया किसान सभा, कलकत्ता 1974, पृ0 82.
09. बिहार सरकार; प्रथम पखवारे की पाक्षिक रपट, अप्रैल 1942.
10. वही.
11. बिहार सरकार, प्रथम पूर्वार्द्ध की पाक्षिक रपट, मई 1942.
12. बिहार सरकार, द्वितीय पूर्वार्द्ध की पाक्षिक रपट, मई 1942.
13 वही.
14. बिहार सरकार, प्रथम पूर्वार्द्ध की पाक्षिक रपट, नवम्बर 1942.
15. वही.
16. वही.
17. डी0 ओ0 नं0 1133, पटना, 8 मई 1943.
18. बिहार सरकार, द्वितीय पूर्वार्द्ध की पाक्षिक रपट, अप्रैल 1943.
19 एम0 ए0 रसूल; उपरलिखित, पृ0 115.

RRIJM 2015, All Rights Reserved